साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 20-26 जनवरी 2025 वर्ष-10, अंक-40

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-पीएम मोदी ने एमपी सहित सात राज्यों के ग्रामीणों को बांटे संपत्ति कार्ड

-मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव भी सिवनी से कार्यक्रम में हुए शामिल

मप्र के 16 लाख लोगों को मिला जमीन का मालिकाना अधिकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों के लाखों ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का ई-वितरण किया। मध्य प्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड मिले हैं।

देशभर के 65 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड देने का काम किया। केंद्र की इस योजना के चलते 5 साल में डेढ़ करोड़ लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला है, जिससे विवाद नहीं होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थी, ये अपने आप में इतना व्यापक और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप सभी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक ने सहभागिता की।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन

दूर होंगी पंचायतों की मुश्किलें

पीएम ने कहा कि अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होंगी और वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगी. इससे आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना भी आसान होगा। स्वामित्व और भू-आधार... ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली हैं। भू-आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। मोदी ने कहा कि करीब 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। बीते 7-8 साल में ही करीब 98 प्रतिशत लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। महात्मा गांधी कहते थे- भारत गांवों में बसता है, भारत की आत्मा गांवों में हैं. पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है।

पुरानी सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए

पुरानी सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 2014 में हमारी सरकार बनी, तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने को ठानी और हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन से देश के गांव में घरों, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती रही है और ये चुनौती है- प्रॉपर्टी राइट्स की।

धान खरीद में बालाघाट,सतना कटनी और रीवा अव्वल

प्रदेश में अब तक खरीदी गई 40 लाख मीट्रिक टन धान

जागत गांव हमार, भोपाल।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6 लाख 22 हजार किसानों से 40 लाख 37 हजार 274 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान का उपार्जन 23 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपए है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में अभी तक 6489 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। खरीदी गई धान में से 32 लाख 84 हजार 233 मीट्रिक टन उपार्जित धान का परिवहन किया जा चुका है। कुल 9 लाख 27 हजार मीट्रिक टन धान मिलर्स को भेजी जा चुकी है। प्रदेश के बालाघाट में 5 लाख 19 हजार 133, सतना 3 लाख 83 हजार 660, कटनी 3 लाख 93 हजार 602, रीवा 3 लाख 36 हजार 573, जबलपुर 3 लाख 48 हजार 522, सिवनी 2 लाख 72 हजार 773, मंडला 1 लाख 88 हजार 464, शहडोल 1 लाख 82 हजार 963, मैहर 1 लाख 58 हजार 350, नर्मदापुरम 1 लाख 53 हजार 844, सिंगरौली 1 लाख 34 हजार 24, पन्ना 1 लाख 42 हजार 881, उमरिया 1 लाख 21 हजार 145, सीधी 1 लाख 16 हजार 530, अनूपपुर 90 हजार 763, मऊगंज 91 हजार 418, दमोह 78 हजार 273, नरसिंहपुर 72 हजार 134, डिंडोरी 65 हजार 519, रायसेन 44 हजार 935, बैतूल 42 हजार 108, सीहोर 34 हजार 757, सागर 16 हजार 554, छिन्दवाड़ा 11 हजार 371, भिंड 1664, विदिशा 1168, हरदा 1212, शिवपुरी 731, मुरैना 129, अलीराजपुर 56 और झाबुआ जिले में 18 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।

मप्र में समर्थन पर गेहूं खरीदी का आज से रजिस्ट्रेशन

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का आनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से प्रारंभ होगा। उपार्जन के लिए चार हजार केंद्र बनाए जाएंगे। यह बात प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता। संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ उपार्जन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में दी। केंद्रीय मंत्री जोशी बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े थे। इस पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की मेकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए मशीन लगाना प्रस्तावित है। इससे खराब गेहूं की खरीदी पर अंकुश लगेगा। समितियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। कहा कि गेहूं और चावल के द्वितीय त्रैमास के प्रावधानित अनुदान की लंबित राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए।

पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव में मप्र के दल को मिला पुरस्कारए, मप्र के पशुपालन मंत्री ने दी बधाई

राष्ट्रीय पशुधन मिशन में मध्यप्रदेश बना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट

जागत गांव हमार, भोपाल।

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने इस उपलब्धि के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी और आशा व्यक्ति की है कि भविष्य में भी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल रहेगा। केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित एक दिवसीय उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार मध्यप्रदेश के दल को प्रदान किया। प्रदेश से योजना के नोडल अधिकारी डॉ. भगवान मधनानी, डॉ. शिवदत्त श्रीवास्तव और डॉ. प्रखर भार्गव, उप संचालक ने पुरस्कार प्राप्त किया। केन्द्रीय सचिव, पशुपालन एवं डेयरी अल्का उपाध्याय, पशुपालन आयुक्त डॉ.अभीजीत मिश्रा और डॉ. पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी द्वारा भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के अधिकारियों को बधाई दी गई है।

अनुदान की किश्त भी मिली

राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश में अभी तक 4800 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 530 प्रकरणों में राशि 387.23 करोड़ रुपए बैंकों से स्वीकृत होकर केन्द्र द्वारा 450 प्रकरणों में 155.36 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत प्रकरणों में 250 उद्यमियों को प्रथम किश्त और 32 को द्वितीय किश्त की अनुदान राशि स्वीकृत होकर प्राप्त हो चुकी है जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

पशु आहार के लिए धार को सम्मान

पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत धार जिले की बदनावर तहसील में स्थापित एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. को पशु आहार केटेगरी में सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में स्थापित बेकरविले स्पेशलिटिस प्रा.लि. को दुग्ध प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन केटेगरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इन दोनों इकाइयों की ऑनलाइन लॉन्चिंग भी केंद्रीय राजीव रंजन सिंह द्वारा कार्यक्रम स्थल से की गई।

मप्र के उत्कृष्ट उद्यमी भी हुए सम्मानित

कॉन्क्लेव में पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और केन्द्रीय उद्यमिता विकास योजनाओं राष्ट्रीय पशुधन मिशन-उद्यमिता विकास कार्यक्रम और पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि अंतर्गत लाभांवित उद्यमियों में से उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाईयों को भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मप्र के जीत सिंह सिसोदिया (भोपाल), नवनीत जैन (हरदा) को चारा उत्पादन के लिए, शोभा दांगी (राजगढ़) और निर्मिला चावड़ा (शाजापुर) को बकरी पालन, यशपाल खन्ना (कटनी) को मुर्गी पालन अंतर्गत उत्कृष्ट उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने सहकार्यता अनुबंध पर दी सहमति

पशुपालकों की आय दोगुनी और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का फैसला

जागत गांव हमार, भोपाल।

प्रदेश की मोहन सरकार लगाता किसानों की आय को दुगुना के प्रयास में लगी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहाना है कि पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही किसानों की दैनिक आमदनी का अच्छा जरिया है। जिसको देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने के साथ ही राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सरकार ने सहकार्यता अनुबंध पर सहमति दे दी है।

मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी गयी।

यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे कलेक्शन सेंटर

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के अनुसार दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जायेगा।

6 से बढ़ाकर 9 हजार की जाएगी समितियों की संख्या

प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। इस तरह दूध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वाषिज्क आय 1700 करोड़ रुपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रुपए किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची ब्रांड का और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा।

30 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा सौर ऊर्जा से : मुख्यमंत्री

अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा पम्प उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने यह बात मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बनायें।

30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए बनाई जाएगी योजना: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सुनियोजित कार्य-योजना बनायें। इसकी समय-सीमा तय होना चाहिये। इससे बिजली सब्सिडी में भी कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध करायें।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संगठनात्मक संरचना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ट्रांसफार्मर एवं बिजली लाइनों के मेंटीनेंस की कार्य-योजना बनाने और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन देने की बात कही।

उर्वरक की खपत में होगी 50 फीसदी से ज्यादा बचत, वैज्ञानिकों का कमाल

अब बिना मिट्टी की खेती, कम पानी में भी फसलों में होगा अच्छा उत्पादन

जागत गांव हमार, भोपाल।

बढ़ते शहरीकरण के कारण जमीन का बंटवारा हो रहा है। जमीन कम होती जा रही है। जो जमीन है उसकी उत्पादकता कम हो रही है। इसलिए किसान परेशान है। पर अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र के बारामती के कृषि विज्ञान केंद्र ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड्स तकनीक की मदद से मिट्टी के बिना खेती करने का आसान तरीका शुरू किया है। इस तकनीक की मदद से किसान बिना मिट्टी के और कम पानी में फसलों की ज्यादा उपज ले सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के आठ अलग-अलग प्रकार किसानों को देखने मिल रहे हैं। पहला प्रकार है ए फ्रेम, एनएफटी, फ्लैट बेड, एग्रोनॉमिक्स, डीडब्ल्यूसी जिसे हम डीप वॉटर कल्चर कहते हैं। इसके अलावा इनडोर ग्रो लाइट और डच बकेट जैसी विभिन्न प्रणालियां दिखाई गई हैं। इस तकनीक में किसान पानी में या कोकोपीट (नारियल का भूसा) जैसी खेती के विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। जहां-जहां जमीन है। जिन भूमि पर उत्पादन नहीं होता है, जैसे कि पथरीली जमीन है, वहां इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीक खासकर शहरों में ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है जहां जमीन कम है और घरों के आंगन में इस तरह की खेती करना बहुत ही आसान हो सकता है।

क्या कहते हैं वैज्ञानिक

इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यशवंत जगदाले ने किसान तक से बात करते हुए कहा कि एयरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक तकनीक में फसल का जमीन से कोई संबंध नहीं होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि मिट्टी से होने वाली बीमारियां फसल के संपर्क में नहीं आती हैं। इसलिए फसलों में रोग होने की संभावना नहीं रहती है। नियमित तरीकों की तुलना में फसल उत्पादन में 30 से 35 फीसदी की वृद्धि होती है। यह तकनीक सब्जी की श्रेणी में अधिक इस्तेमाल की जा रही है। सब्जियां और फल की श्रेणी में सलाद पत्ता, पालक सब्जी है, फल वाली सब्जी में खीरा, शिमला मिर्च लगाते हैं।

हाइड्रोपोनिक्स से खेती

अब, पिछले एक-दो सालों में, ज्यादा से ज्यादा किसानों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार भी इसके लिए सब्सिडी शुरू करने का विचार कर रही है। हालांकि अभी सब्सिडी शुरू नहीं हुई है। इस तकनीक में किसानों को सब्सिडी देने के लिए सरकारी दिशा-निर्देश बना लिए गए हैं। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में इस तकनीक की आठ अलग-अलग प्रणालियां बना ली हैं। तो, प्रत्येक प्रणाली की लागत और यह कितना क्षेत्र कवर करती है, उसके अनुसार अनुमान है कि औसत लागत कम से कम 1800 रुपए प्रति मीटर होगी और अधिकतम लागत 2500 रुपए होगी।

काम आएगी नीदरलैंड्स की तकनीक

यशवंत जगदाले ने कहा, नेदरलैंड्स और इजराइल तकनीक की मदद से मिट्टी के बिना खेती का प्रयोग सफल रहा है। खास बात यह है कि जो स्ट्रॉबेरी शीतकालीन वातावरण में उगाई जाती है। वह देश के किसी भी कोने में इस तकनीक की मदद से किसी भी ऋतु में उगाई जा रही है। इस नियंत्रित वातावरण में हम साल भर स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का आकार और मिठास मिट्टी से भी ज्यादा होती है।

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती

हाइड्रोपोनिक फसल उत्पादन विधियों में फसल उर्वरक को रिसाइकिल करते हैं। साथ ही इसमें लगने वाले पानी को भी रिसाइकिल करते हैं जिसका उपयोग पौधे विकास के लिए करते हैं। इससे उर्वरक की कम से कम 50 फीसदी बचत हो सकती है। इसलिए यह तकनीक उपयुक्त है। जमीन का संपर्क न होने के कारण किसानों को अधिक से अधिक उपज मिलेगी और फायदा भी दोगुना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को कोल्ड स्टोरेज और रायपनिंग चेंबर देगी अनुदान

जागत गांव हमार, भोपाल।

फल, सब्जी एवं अन्य नश्वर उत्पादों का भंडारण कर किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज एवं रायपेनिंग चेम्बर बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा राज्य के चयनित जिलों में कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 और रायपेनिंग चेम्बर के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कितना अनुदान मिलेगा: एमपी के छिंदवाड़ा जिले के उप संचालक उद्यान एम.एल.उईके ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की केन्द्र पोषित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतगत्त फसलोत्तर प्रबंधन घटक के तहत कोल्ड स्टोरेज टाईप-1, 5000

मीट्रिक टन क्षमता पर 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 140.00 लाख रुपए एवं रायपनिंग चेम्बर 300 मीट्रिक टन क्षमता के भौतिक लक्ष्य उपलब्ध है जिस पर लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 105.00 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

कहाँ आवेदन करें: उद्यानिकी विभाग, छिंदवाड़ा के उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक हितग्राही विभागीय mpfts पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक को डी.पी.आर., बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, बैंक एप्राइजल रिपोर्ट, भूमि के दस्तावेज, भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण पत्र, चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट, केन्द्र व राज्य सरकार से पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं करने का घोषणा पत्र 100 के नोटराइज्ड स्टांप पर एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानकों और मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराने का घोषणा पत्र 100 के नोटराइज्ड स्टांप पर सहित परियोजना प्रस्ताव/आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन की हार्डकापी संबधित विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

सीएम बोले-वनोपज की जरूरत व उपलब्धता में अंतर बढ़ा

वन, वन्य-जीव संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी है मध्यप्रदेश

बफर-सफर योजना के तहत कई गतिविधियों की शुरुआत

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश के वन और वन्य-जीव हमारी पहचान हैं। शासन इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये की गई ईमानदार एवं प्रभावी पहल का परिणाम है कि वन आवरण में स्थायित्व आने के साथ ही वन्य-प्राणियों के प्रबंधन की दिशा में अनेक नवाचार किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग ग्रामीण अंचलों में विकास गतिविधियों का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है। विगत दो दशकों में वन प्रबंधन में काफी बदलाव आए हैं। वन संसाधनों पर जैविक दबाव बढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ वनोपज की आवश्यकता और उपलब्धता में अंतर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को कड़ाई से रोका जा रहा है। वनोपज की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए विभागीय रोपण के साथ निजी वनीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन तथा वन्य-जीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिये वन महोत्सव, अनुभूति, वन्य-प्राणी और संरक्षण सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है।

आकर्षित हो रहे सैलानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बफर-सफर योजना के तहत पर्यटकों के लिए अनेक नई गतिविधियां प्रारंभ की गयी हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में पर्यटक प्राकृतिक स्थलों, वन और वन्य-प्राणी दर्शन के साथ विभिन्न ईको-पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। ईको-पर्यटन से पर्यटक प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। इससे कोर क्षेत्र पर पर्यटन का दबाव भी कम होगा। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 15 हजार से अधिक वन समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की कार्य-प्रणाली को और अधिक गतिशील बनाया जा रहा है।

वनवासियों का संरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन प्रबंधन में ग्रामीणों की सहभागिता को अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने तथा संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए इसे कानूनी आधार देने की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसमें वनोपज से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय प्राथमिक वनोपज समितियों को हस्तांतरित करने की पहल की गई है। इस व्यवस्था से वनवासियों के हितों का संरक्षण हुआ है। वहीं गरीब वनवासियों का बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को भी रोका गया है।

रोजगार भी मिल रहा

वनोपज की शुद्ध आय के एक अंश से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हमारा प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जहां वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है और वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वनवासियों को वनोपज के प्र-संस्करण से भी जोड़ा गया है। इससे वनवासियों को संग्रहित वनोपज की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हो रहा है।

39 नगर-वन स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वन आवरण में 1063 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश नगर-वन योजना में देश में अग्रणी है। इस वर्ष 39 नगर-वन स्वीकृत किए गए हैं। उज्जैन, चित्रकूट, खजुराहो और भोपाल में सांस्कृतिक वनों की स्थापना की जा रही है। ई-प्रणाली के माध्यम से समस्त काष्ठागारों में वनोपज की नीलामी प्रारंभ की गयी है। वन विभाग द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान में लगभग 6.16 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं। प्रदेश में 16.09 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध 16.68 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया और तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में 667.20 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

तेंदूपत्ता बोनस वितरण का लक्ष्य

पेसा एक्ट में 243 ग्राम सभाओं ने 22 हजार 212 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण कर 11.36 करोड़ का व्यापार किया है। वर्ष 2024 में 125 करोड़ का तेंदूपत्ता बोनस वितरण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिये 57 वन-धन विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष-2025 के रोपण के लिये वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन्य-प्राणियों की पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली को वेब आधारित किया गया है। चीता परियोजना के द्वितीय चरण में गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में चीता लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही माधव राष्ट्रीय उद्यान को एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व बनाने की सहमति दे दी गयी है।

मंत्री बोले-उपभोक्ता हितैषी बनाने की अभिनव पहल

दुकानें होगी वित्तीय रूप से सशक्त, इंदौर की 30 राशन दुकानों पर खुलेंगे जन पोषण केंद

जागत गांव हमार, भोपाल।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय रूप से सशक्त करने और उपभोक्ता हितैषी बनाने की अभिनव पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर शहर की 30 चयनित उचित मूल्य दुकानों में जन पोषण केंद्र खोले जाएंगे। इन केन्द्रों से पोषण से जुड़े गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। मंत्री राजपूत ने बताया किजन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आय का एक और जरिया मिल सकेगा। केंद्रों में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

जन पोषण केंद्रों से फायदे

केंद्रों से राशन डीलरों की आय बढ़ेगी। लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी। राशन डीलरों को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत मप्र में इंदौर जिले की 30 राशन दुकानों का चयन किया गया है। दुकानों के डीलर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण 13 से 17 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नंदा नगर, सुखलिया में किया गया।

प्रशिक्षण दिया गया

प्रशिक्षण में उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकान पर जन पोषण केंद्र की स्थापना, पीडीएस की सामग्री के अलावा अन्य सामग्री विक्रय, पोषण संबंधी वस्तुएं प्राथमिकता से विक्रय करने, उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने, भंडार संचालक को अतिरिक्त सामग्री बिक्री से आमदनी कैसे बढ़े और आम उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं सुलभ प्राप्त हो सके का, आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।

सर्टिफिकेट वितरित

प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में भारत सरकार के अवर सचिव मंजुला डेनियल एवं अभिषेक कुमार कंसलटेंट द्वारा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला आपूर्ति नियंत्रक इंदौर एमएल मारू द्वारा भी विक्रेताओं को उचित मार्गदर्शन किया गया। प्रशिक्षण पश्चात सभी विक्रेताओं का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, इसके बाद सर्टिफिकेट वितरित किए गए।

फायदेमंद है कड़कनाथ पालन, वजन कम होने के बाद भी 20 रुपए का

जागत गांव हमार, भोपाल।

अंडे की क्वालिटी किस पैमाने पर मापी जाए इसके लिए आम ग्राहकों के पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन पोल्ट्री बाजार में अंडे के दाम उसके साइज और वजन के हिसाब से तय होते हैं। हाल ही में भारत से अंडा खरीदने वाले कतर ने नई शर्तों के हिसाब से अंडा खरीदने की बात कही है। कतर की नई शर्तों में अंडा का वजन प्रमुख है, लेकिन एक अंडा ऐसा भी है जो वजन में कम होने के बावजूद महंगा बिकता है और ये अंडा है कड़कनाथ मुर्गी का। कड़कनाथ मुर्गी का अंडा ही नहीं चिकन भी महंगा बिकता है। हालांकि पोल्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक अंडा और चिकन महंगा बिकने के पीछे कई वजह है। बिहार एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी, पटना ने भी कड़कनाथ के चिकन और अंडे को लेकर कई दावे किए हैं। रेट और खासियत के चलते ही अब देशभर में कड़कनाथ का पालन किया जा रहा है। पोल्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि कड़कनाथ मुर्गी 6 महीने की उम्र पर पहला अंडा देती है। कड़कनाथ के अंडे का वजन 45 ग्राम होता है। जबकि 55 ग्राम और उससे ज्यादा वजन का अंडा ज्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि बाजार में सात से आठ रुपये का बिकने वाला सफेद अंडा 50 से 55 ग्राम तक का होता है। सामान्य सफेद मुर्गी जहां एक साल में 190 से लेकर 210 तक अंडे देती है। वहीं कड़कनाथ मुर्गी एक साल में 120 अंडे ही देती है। कड़कनाथ मुर्गी का अंडा बाजार में 20 से 25 रुपए का बिकता है।

जान लें कड़कनाथ के बारे में

- कड़कनाथ नस्ल के चिकन में 25 फीसद प्रोटीन होता है, जबकि अन्य में 18 से 20 फीसदी
- कड़कनाथ में फैट की मात्रा 0.73-1.03 फीसद और अन्य में 13-25 फीसद होती है
- कड़कनाथ में कोलेस्ट्रोल की मात्रा 184 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम चिकन होती है
- अन्य नस्ल में कोलेस्ट्रोल की मात्रा 218 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम चिकन होती है
- कड़कनाथ नस्ल के चूजे का वजन 28-30 ग्राम तक होता है
- कड़कनाथ के शरीर का रंग काला होता है
- आठ हफ्ते की उम्र पर कड़कनाथ का वजन 800 ग्राम हो जाता है
- व्यस्क कड़कनाथ मुर्गे का वजन 2.2 से 2.5 किग्रा तक हो जाता है
- व्यस्क कड़कनाथ मुर्गी का वजन 1.5 से 1.8 किग्रा तक हो जाता है
- कड़कनाथ मुर्गे को हलाल करने पर 65 फीसद चिकन निकलता है
- कड़कनाथ मुर्गी हर महीने 11 से 13 अंडे देती है

गाय/भैंस पालनः आमदनी दुगुनी करने के लिए एक कदम

› डा. अनिल रिदे
› डा. लक्ष्मी चौहान
› डा. प्रमोद शर्मा
› डा. भावना चौहान
- पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में पानी की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हम पूर्णतः खेती पर निर्भर नहीं रह सकते। खेती के साथ-साथ पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन को भी सहायक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। ज्यादातर किसान या मजदूर भाई एक या दो देसी जानवर पारम्पारिक तरीके से पालते हैं। उनसे प्राप्त दूध को घर में उपयोग करते हैं या पड़ोस में बेचते हैं। जानवरों को उचित स्वास्थ्य सुविधा, संतुलित आहार न मिल पाने के कारण दुग्ध व्यवसाय का फायदा दिनों-दिन कम होता जा रहा है।

अगर हमें अपने जानवरों की उत्पादकता बढ़ानी है तो उच्चत्तम गुणवत्ता के वीर्य, संतुलित आहार, चारा और स्वास्थ्य प्रबंधन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तथापि वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रबंधन एवं अपने पास के उपलब्ध साधन का परिणाम कारक उपयोग करना अनिवार्य है।

गाय/भैंस पालनः खेती के साथ सहायक आय स्त्रोत के रूप में उन्नत नस्ल की गाय अथवा भैंस पालन लघु व सीमांत किसानों के लिए अच्छे व्यवसाय है। दुधारू जानवरों से दूध, घी, दही इत्यादि प्राप्त होने के अलावा उत्तम जैविक खाद एवं घरेलू ईंधन भी बायोगैस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे हम कम लागत में अधिक उत्पादकता ले सकते हैं।

आवास व्यवस्थाः (1) जानवरों का आवास सूखी समतल जगह पर होना चाहिए जिसकी दीवार 5-6 फीट ऊंची और छत 10-12 फीट ऊंचाई पर होनी चाहिए। (2) आवास का फर्श सूखा, समतल एवं उचित ढलान वाला हो जिस पर पानी एकत्रित न हो और मध्य में नाली बनानी चाहिए। (3) आजकल मुक्त संचार शेड ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं जिसमें 30 प्रतिशत जगह पर छांव या बारिश से बचने के लिए शेड बनाया जाता है और बाकी की जगह खुली रखी जाती है जिसमें जानवर टहल सकते हैं। उसी में पानी और चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें मेहनत और लागत भी कम लगती है।

आहार व्यवस्थाः पशुओं का 60-70 प्रतिशत खर्चा चारे की व्यवस्था पर आता है। इसलिए हमें हमारे पास उपलब्ध चारे का प्रभावशाली उपयोग करना चाहिए। जैसे की गर्मी के दिनों में हरे चारे की कमी महसूस होती है। उसके लिए साइलेज (हरे चारे का आचार) बना सकते हैं। चना, गेहूं या धान का भुसा

जिसको ज्यादातर किसान फेक या जला देते हैं उस पर यूरिया उपचार (4 प्रतिशत) करके उसको अच्छा प्रोटीन स्त्रोत बना सकते हैं और उससे 30 प्रतिशत चारे की बचत भी कर सकते हैं। पशुओं को हरा और सूखा चारा सही मात्रा में देना चाहिए उसी के साथ-साथ जो दुधारू या गाभण जानवर हैं उन्हें संतुलित आहार भी देना चाहिए। मिनरल मिक्चर में आवश्यक क्षारों का योग्य मात्रा में समावेश होता है वह चयापचन कार्य, दूध उत्पादकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

गाय और भैंस के लिए सूखे व हरे चारे की सही मात्रा

1 गाय/भैंस को	सूखा चारा 6 किलो। हरा चारा 15-20 किलो दूध न देने की अवधि में। हरा चारा 20-25 किलो दूध देने की अवधि में।

संतुलित आहार

पशु प्रकार	शरीर रक्षण	5 लीटर दूध के लिए	कुल उत्पादकता के लिए
गाय	2 कि.ग्रा.	2 कि.ग्रा.	4 कि.ग्रा.
भैंस	2 कि.ग्रा.	2.5 कि.ग्रा.	4.5 कि.ग्रा.
गाभण गाय/भैंस	2 कि.ग्रा.	2 कि.ग्रा.	4 कि.ग्रा.

चारा कटाई मशीन का इस्तेमाल करके चारा काट कर के देने से वेस्टेज कम हो जाती है और चयापचन कार्य भी बढ़ता है।

प्रजनन व्यवस्थाः गाय और भैंस का कृत्रिम गर्भाधान उच्च नस्ल वाले सांड के वीर्य से करना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान से शारीरिक बीमारियां दूर रहेगी। अच्छे नस्ल वाले सांड के कारण आने वाली संताने भी अच्छी रहेगी। सभी पशुओं के मदकाल में आने का पता रखना चाहिए एवं उसकी अवधि, गर्भाधान, गर्भाधारण की तिथि, ब्याने की तिथि का रिकार्ड रखना चाहिए। ब्याने के बाद 65-80 दिनों के भीतर पशुओं में मदकाल आरंभ हो जाता है। मदकाल के 12 से 24 घंटों के बीच गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान के 18-21 दिन बाद अगर गर्भधारणा नहीं हुई तो गाय/भैंस फिर मदकाल पे आती है। इसलिए उस समय ध्यान देना चाहिए। गर्भाधान के 85-90 दिनों के बाद गर्भाधारणा की जांच करानी चाहिए। अगर लगातार 8 गर्भाधन से गर्भाधारणा नहीं हुई तो निकटतम पशुचिकित्सक से उसकी जांच करवानी चाहिए।

गर्भावस्थाः ब्याने के 2-3 माह पूर्व गाभण गायों व भैंसों को पर्याप्त स्थान, आहार, हरा चारा, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 6-8 महीने बाद गायों व भैंसों को चरने हेतु बाहर ज्यादा दूर नहीं छोड़ना चाहिए। 8 महीने बाद उनका दूध निकालना बंद करना चाहिए। कैल्शियम और संतुलित आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

बछड़े की देखभालः नवजात बछड़े को पहला गाढ़ा पीला दूध अवश्य पिलाना चाहिए। वह विशेष पोषक तत्व तथा एंटीबॉडी युक्त होने के कारण रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है।

संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशुओं का टीकाकरण कार्यक्रम

रोग का नाम	शुरूआत कार्यनीति	बाद में	टिप्पणी
खुरपका मुहपका	4 माह	प्रत्येक 6 माह पर	फरवरी-मार्च/अगस्त-सितम्बर
एंथ्रेक्स		6 माह	साल में एक बार महामारी क्षेत्र में
लंगड़ी बुखार	6 माह	साल में एक बार	बारिश के मौसम की शुरूआत से पहले रक्त स्त्रावित
सैप्टीसीमीया (गलघोटू)	6 माह	साल में एक बार	बारिश के मौसम की शुरूआत से पहले
ब्रूसेलोसिस (संक्रामक गर्भपात)	6 माह	3 या 4 ब्यान तक	यह नर को नहीं लगाया जाता

स्वास्थ्य प्रबंधनः जैसे कि हम जानते हैं कि उपचार से भला है बचाव, इस कारण हमें हमारे पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए टीकाकरण करना अति आवष्यक है। असामान्य बर्ताव जैसे कि कम आहार लेना, बुखार, अधिक स्त्राव इत्यादि बीमारी के लक्षण है, ऐसा दिखाई देने पर पशुओं को निकटतम पशुचिकित्सक से दिखाकर उपचार करवाना चाहिए। थनैला, ब्रूसेलोसिस, टी.बी. आदि रोगों का नियमित रूप से परीक्षण करवाते रहना चाहिए। संक्रामक रोगों से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए।

भिंड जिले के ग्राम गिरवासा की बदली तस्वीर, प्रदर्शन के परिणामस्वरुप ज्वार फसल के क्षेत्रफल में 90 प्रतिशत तक का इजाफा

निकराः जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल परियोजना

कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड) पर वर्ष 2022-23 से जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निकरा) परियोजना की शुरुआत हुई। परियोजना के तहतः वर्ष 2023-24 में लहार विकासखंड के गांव गिरवासा की प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए गांव को अंगीकृत किया गया। परियोजना के अंतर्गत गांव को अंगीकृत करने में कृषि प्रणाली टोपोलॉजी वर्षा आधारित को मध्येनजर रखते हुए गांव का चयन किया गया था। गिरवासा गांव में कुल खेती योग्य भूमि 631.59 हेक्टेयर है। जिसमें वर्षा पर आधारित क्षेत्रफल 252.64 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) तथा सिंचित क्षेत्र 378.95 हेक्टर (60 प्रतिशत) है. गांव में कुल 625 परिवार रहते हैं, जिसमें से परियोजना के तहतः 45 परिवारों के साथ कार्य किया गया. जिले की औसत वर्षा 668 मिली मीटर को ध्यान में रखते हुए गांव में वर्षा आधारित क्षेत्र में खेती करने पर विशेष जोर दिया गया।

इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख एवं परियोजना अन्वेषक डॉ. एसपी सिंह द्वारा गांव में खरीफ 2023 में किसानों का चयन कराकर 15 हेक्टर क्षेत्रफल में कृषि प्रणाली पशुओं के साथ वषाज़ आधारित टोपोलॉजी के अंतगज़्त ज्वार की खेती कराई गई। जिसमें परियोजना के तहतः तकनीकी प्रदर्शन के अंतर्गत किसानों के खेतों में राज विजय ज्वार 1862 (RVJ 1862) एवं राज विजय ज्वार 2357 (RVJ 2357) प्रजाति लगवाई गई थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा विकसित एवं जारी की गयी यह नवीनतम प्रजातियां ताप सहनशील अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं।

जिसके परिणामस्वरुप किसानों को बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। गांव में खरीफ मौसम में जहां किसानों के अधिकांश खेत खाली पड़े रहते हैं, वहां परियोजना के तहतः किसानों को ज्वार की खेती के रूप में एक नया विकल्प दिखाई दिया। इसके चलते खरीफ2024 में गत वर्ष के ज्वार की खेती के उत्साह जनक परिणाम से प्रभावित होकर गांव में क्षेत्र विस्तार करके कई किसानों

द्वारा 105 हेक्टर भूमि पर ज्वार की खेती की गई। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के क्षेत्रफल का क्षैतिज प्रसार 90 प्रतिशत तक हुआ जोकि एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा सकता है।

परियोजना के तहत गिरवासा गांव में ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति ग्राम स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करना है।

समिति के अध्यक्ष गांव के किसान विनोद दुबे ने बताया कि उनके गांव में सिंध नदी के कटाव से भूमि ऊंची नीची तथा समतल नहीं हैं। इस भूमि पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण इस जमीन पर किसान खेती नहीं कर पाते थे लेकिन परियोजना के प्रयासों से इस भूमि पर भी खेती कर पाना संभव हुआ है। समिति के सचिव गोविंद सिंह का कहना है खरीफ 2023 में ज्वार की खेती करने से गांव के किसानों को लाभ मिला है तथा किसान स्वयं ज्वार की खेती की ओर इस वर्ष उत्सुक हुए हैं। परियोजना के अंतगज़्त इस वषज़ खरीफ2024 में बाजरा की फसल को भी बढ़ावा दिया गया है।

कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख एवं परियोजना अन्वेषक डॉ. एसपी सिंह बताते है कि ज्वार-बाजरा जैसी मोटे अनाज की फसलें कम पानी, कम उपजाऊ जमीन तथा कम लागत लगाकर पैदा की जा सकती हैं। परियोजना के तहत मोटे अनाज की फसलों को उगाने की तकनीकी एवं वर्षा आधारित खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. वहीं रबी मौसम में इसी भूमि पर कम पानी में पैदा होने वाली फसलें सरसों, चना आदि की खेती कराई जा रही है। निकरा परियोजना में कार्यरत एसआरएफ दीपेंद्र शर्मा का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकरा परियोजना के अंतगज़्त कई सारे कार्य कराए जा रहे हैं जिसका लाभ गांव में वर्षा आधारित खेती करने वाले किसानों को मिल रहा है। परियोजना से पशुपालन करने वाले किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं।

जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल परियोजना

जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निकरा) परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली की एक नेटवर्क परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत पूरे देश में फरवरी 2011 में हुई थी। निकरा परियोजना को संपूर्ण देश में संचालित करने वाला नोडल संस्थान केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में जलवायु अनुकूल तकनीकों को विकसित करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना है। इस परियोजना के जरिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन करना और अनुकूलन रणनीतियों का निर्माण करना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का विकास करना, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का प्रबंध करना एवं वैज्ञानिकों और अन्य हित धारकों की क्षमता को बढ़ाना। निकरा परियोजना अंतर्गत चार मॉडल पर प्रमुखता से काम किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य में सुधार, फसल उत्पादन, पशुधन प्रबंधन एवं मछली पालन एवं किसानों का क्षमता विकास करना प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जंगलों की आग रोकने के लिए परंपराएं तक छोड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी

मप्र में क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा जंगल फैला हुआ है। इसी राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी निवास करती हैं। यहां के वन क्षेत्रों में विविध आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनमें गोंड, बैगा और कोरकू प्रमुख हैं। आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफइंडिया (ट्राइफेड) के अनुसार मप्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में करीब 75 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी आबादी आजीविका के लिए वनोपज पर निर्भर है।

हजारों वनवासी जो मध्य प्रदेश के जंगलों के समीप निवास करते हैं। उनके लिए साल के शुरूआती छह माह किसी त्यौहार से कम नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय वे जंगलों से महुआ, तेंदूपत्ता के साथ अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) जैसे आंवला, साज, करवा चिराग, बीज, सफेद मूसली, अशोक छाल, सेमल, कपास और शहद आदि का संग्रहण करते हैं। ये वनोपज ही उनकी आमदनी का साधन हैं।

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक मप्र के जंगलों में आग लगने की 47,795 घटनाएं हुईं। जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं से वनवासियों को आजीविका, भोजन, दवा के साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए कच्चे माल की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों के खत्म होने से वे जीविका के लिए बाहरीस्रोतों पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

जंगलों में आग लगने के कारणः भारत सरकार द्वारा साल 2018 में शुरू की गई वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना के तहत आग के कारणों का पता लगने और रोकथाम के उपायों के लिए एक अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार ने साल 2019 में आग को आपदा माना और मध्य प्रदेश के 22 जिलों को चिन्हित किया।

बिगड़े काम बनाने जंगल में लगाते हैं आगः आदिवासियों की मान्यता है कि जंगल में आग लगाने से बिगड़े हुए काम हो जाते हैं। लेकिन यही आग विकराल रूप धारण कर लेती है। समुदायों के बीच जन-जागरुकता अभियान, विभिन्न प्रतियोगिताओं और खेल-कूद जैसे तरीकों का सहारा लेकर जागरुकता पहुंचाई जा रही है। जनजागरूकता का परिणाम भी सामने आ रहा है। आदिवासी जंगल को बचाने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को छोड़ रहे हैं। उनको अब यह समझ में आ रहा है किजंगल में लगाई जाने वाली आग से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर, आदिवासियों और वन विभाग के साझा प्रयास स्थिति को बदल रहे हैं।

धनखड़ बोले- किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता

खराब बाजार और मौसम की मार से किसान बेजार

जागत गांव हमार, भोपाल/नई दिल्ली।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि किसानों से जुड़े मुद्दों को समय पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। धारवाड़ में कृषि विज्ञान विवि के अमृत महोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपना संबोधन देते हुए उन्होंने कहा-किसानों की समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है। हम इस देश में यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा पहले कभी इतना नहीं हुआ कि किसानों की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया जाए।

देश का भाग्य विधाता

किसानों की की समस्याओं को हल करने में समय की बहुत अहमियत है। सरकार काम कर रही है, और हमें समाधान खोजने के लिए सकारात्मक सोच के साथ सही दृष्टिकोण की जरूरत है। किसान देश का अन्नदाता है, देश का भाग्य विधाता है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कपड़ा, खाद्य और खाद्य तेल जैसे कृषि आधारित उद्योग समृद्ध हो रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं।

किसानों पर खर्च हो फंड

धनखड़ ने कहा कि हमारे किसानों को इन लाभों में बराबरी के साथ हिस्सा लेना चाहिए। इन संस्थानों को अपने सीएसआर फंड का उपयोग किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र अनुसंधान के लिए करना चाहिए। क्योंकि कृषि उपज उनकी जीवन रेखा है, जिस पर किसान का नियंत्रण है। हमें अपने किसानों को किसी भी कीमत पर खुश रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा-पीएम किसान सम्मान निधि एक खास योजना है, जिसके तहत 100 मिलियन (10 करोड़) किसानों को 3.5 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। उर्वरकों सहित सभी सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे अपने उपयोग का निर्णय ले सकें। डीबीटी किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के विकल्प तलाशने के लिए बढ़ावा दे सकती है।

राहत दिलाने की जरूरत

खराब मौसम और बाजार जोखिम के तनावों से किसानों को राहत दिलाने की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा-कृषि क्षेत्र को तनावों से मुक्त करने और उनका विश्लेषण करने का समय आ गया है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन किसान खराब मौसम, खराब बाजार स्थितियों पर निर्भर है। अगर कमी है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। अगर बहुत कुछ है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है।

तकनीक अपनाने पर जोर

धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र को किसी भी रूप में दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा-कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत है। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लेकिन किसान अभी भी पुराने ट्रैक्टर से चिपके हुए हैं। ट्रैक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकारी सब्सिडी सबसे ज्यादा है। किसान को तकनीक अपनानी चाहिए।

-खेती-उपज के साथ किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य

हल्दी का निर्यात बढ़ाने पर फोकस पांच साल में दोगुना करने का प्रयास

जागत गांव हमार, भोपाल/नई दिल्ली।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अगले 5 साल में हल्दी निर्यात बढ़ाकर दोगुना करने पर काम कर रहा है। स्टडी में कहा गया है कि 2030 तक भारत का टरमेरिक एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। वर्तमान में भारत हाई कर्क्यूमिन वाली हल्दी की वैश्विक मांग का केवल 10 फीसदी ही दे पा रहा है। इसके अलावा किसानों से हल्दी की खरीद में तेजी लाने और उन्हें खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के प्रमुख हल्दी केंद्रों में से एक उत्तरी तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन किया। हल्दी बोर्ड का लक्ष्य 2030 तक हल्दी के निर्यात को 1 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में 58.2 मिलियन डॉलर मूल्य का वैश्विक हल्दी बाजार 2028 तक 16.1 फीसदी की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

हल्दी का रकबा बढ़ाना होगा

स्टडी के अनुसार हल्दी से जुड़े भारतीय किसानों को उतार-चढ़ाव की कीमतों, सीमित बाजार पहुंच और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में 2023-24 में 1,041,730 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 297,460 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करने के बावजूद उत्पादन को मजबूत करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए सुधार की जरूरत है।

जीआई टैग बढ़ाने पर जोर

स्टडी में बताया गया है कि भारत एमआरएल वाली हाई कर्क्यूमिन (5 प्रतिशत से अधिक) हल्दी की वैश्विक मांग का केवल 10 फीसदी ही आपूर्ति करने में सक्षम है। इसलिए हाई कर्क्यूमिन किस्म विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास की जरूरत है। इसके साथ ही ऐसी किस्मों को वैश्विक प्लेटफार्मों पर मार्केटिंग किया जाना चाहिए। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में हैं और 6 जीआई टैग को बढ़ाने की जरूरत है। 5 फीसदी से अधिक करक्यूमिन वाले उत्पादों में जीआई को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

एक बिलियन डॉलर होगा निर्यात

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक मिश्रा ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अनुमान है कि भारत का हल्दी निर्यात 2030 तक 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी स्थापना की है। इस संदर्भ में हमारी रिपोर्ट इस बारे में लक्षित सिफारिशें करती है कि कैसे भारत वैश्विक हल्दी उत्पादक और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

हल्दी विरासत का लाभ उठाने की जरूरत

स्टडी की प्रमुख ऑथर डॉ. अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि उत्पादन को बढ़ाने, निर्यात चैनलों को मजबूत करने और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के माध्यम से अपनी समृद्ध हल्दी विरासत का लाभ उठाने के लिए भारत के अनूठे अवसर पर जोर दिया। भारत को हल्दी का वैश्विक केंद्र बनाना किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, कंपनियों और नीति निर्माताओं की अंतर्दृष्टि को ध्यान से दर्शाती है। रिपोर्ट देश में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने पर विचार करती है ताकि किसानों की आय बढ़े और एमएसएमई को लाभ मिले।

41 हजार किसानों से 3.37 लाख टन धान खरीदी

जबलपुर में किसानों को 487 करोड़ का भुगतान

जागत गांव हमार, जबलपुर।

जबलपुर में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी में किसानों को अब तक 487 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 2 दिसंबर से शुरू हुई खरीदी में 41,481 किसानों से लगभग 3.37 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। जिले में कुल 86 से अधिक खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां 55,928 किसानों ने पंजीयन कराया है। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक दिलीप किरार के अनुसार, 23 जनवरी तक चलने वाली इस खरीदी में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों द्वारा लगातार स्लॉट बुकिंग की जा रही है, जिससे लक्ष्य से अधिक खरीदी की संभावना है। किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। ईपीओ प्राप्त होते ही तत्काल भुगतान किया जा रहा है।

बोई गई फसलों को एमपी किसान एप पर दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी

15 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सुधार करवा सकते हैं

जागत गांव हमार, खंडवा

मध्य प्रदेश शासन की कृषि संबंधी योजनाओं हेतु रबी फसल गिरदावरी वर्ष 2024-25 में 28 फरवरी तक जिले के समस्त कृषक अपनी-अपनी भूमि में बोई गई फसलों को स्वयं एम.पी. किसान एप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।

भू अभिलेख अधीक्षक ने बताया कि इसके साथ ही पटवारी/सर्वेयर द्वारा दर्ज की गई फसल की जानकारी देख सकते हैं एवं यदि गिरदावरी में भिन्नता पाई जाती है तो कृषक या भूमि स्वामी स्वयं एमपी किसान ऐप के माध्यम से 15 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सुधार करवा सकते हैं। जिससे उपार्जन आदि में विसंगति न हो एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कृषकों को प्राप्त हो सके।

गांव के शिक्षक की बेटी ने एमपीपीएससी में लाई नवमी रैंक बढ़ाया टीकमगढ़ जिले का मान, घर पहुंच लोग दे रहे बधाई

अखण्ड यादव। टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है देवी नगर जहां की एक शिक्षक की बेटी ने मध्य प्रदेश की पीएससी परीक्षा में नवमी रैंक हासिल की है कविता यादव रहती हैं जिन्होंने यह सफलता बिना कोचिंग के हासिल की है और पहली बार मध्य प्रदेश की पीएससी परीक्षा में वह बैठी थी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह टॉप टेन में जगह ले पाएंगे लेकिन इतना विश्वास जरूर था कि वह एमपीपीएससी को इस साल जरूर निकालेंगे । और मध्य प्रदेश में 9 वी रेंक मिली हैं। कविता यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी प्राथमिक शिक्षा टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ नगर में हुई । इसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की शिक्षा टीकमगढ़ में हुई है और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद उसने ग्रेजुएशन का निर्णय इंदौर में जाने का लिया इंदौर में रहकर के उसने साइंस कॉलेज से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करने का निर्णय लिया बीएससी करने के बाद वह अपने रूम में रहकर के करीब 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करती थी ना उसने कोचिंग ली और ना किसी कोचिंग में एडमिशन लिया इसके बाद मध्य प्रदेश की

पीएससी में नवमी रैंक हासिल की है। कविता यादव ने बताया कि इस सफलता का उसके पिता शिक्षक और मां के साथ-साथ भाइयों को जाता है। क्योंकि पिता ने हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया है उसने बताया कि वह प्रतिदिन करीब 8 से 12 घंटे घर पर रहकर के सेल्फ स्टडी करती थी जिस कारण से उसे सफलता मिली है उसका मानना है कि सफलता उसके परिजनों के सहयोग के कारण संभव हो चुकी है।

पहली बार एमपीपीएससी टॉप टेन में मिली जगह

टीकमगढ़ जिले के देवी नगर गांव में जन्मी बेटी ने पहली बार एमपीपीएससी में टॉप टेन में जगह बनाई है कविता यादव का कहना है कि उसने बिना कोचिंग के यह स्थान हासिल किया उसने कहा कि वह 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी अपने रूम पर करती थी कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी उसको ग्रहण करती थी इसके बाद वह अपने रूम पर आकर के 8 से 10 घंटे रूम पर एमपीपीएससी की तैयारी करती थी उसने किसी भी कोचिंग को गाइड का सहारा नहीं लिया उसने बताया कि वह पहली बार उसने मध्य प्रदेश की पीएससी में भाग लिया था।

पहली बार मिली सफलता

कविता यादव का कहना है कि वह 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई कर रही थी लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसका मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी टॉप टेन में नाम आएगा उसे उम्मीद थी कि वह एमपीपीएससी में जरूर सफल होगी। अपने शिक्षक पिता और मां को देती है उसने कहा कि पिता ने हमेशा शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया है जिस कारण उसे सफलता मिली है वह आने वाले एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कहती हैं की सबसे पहले वह अपना क्लियर करें कि वह किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं और इसके साथ ही वह सामाजिक और खेलकूद में जरूर भाग ले लेकिन अपना लक्ष्य बनाकर निर्धारित करे जिससे कि उन्हें सफलता मिल सके इसके लिए जरूरी नहीं है कि वह किसी कोचिंग सेंटर में जाए बल्कि वह अपना लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो जब सफलता जरूर मिलेगी ।

65 दलहन बीज केंद्र और 50 स्टोरेज यूनिट बनेंगी, मॉडल दलहन गांव प्रोजेक्ट को मंजूरी

नई दिल्ली। । जागत गांव हमार

केंद्र सरकार दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजी से काम कर रही है। दलहन के लिए आईसीएआर के केवीके के जरिए 10,780 हेक्टेयर में दालों के क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन नीति अपनाई जा रही है। जबकि खरीफ 2024 के लिए दालों की 4 l25 लाख मिनीकिट और रबी 2024-25 के लिए दालों की 22.17 लाख मिनीकिट किसानों को आवंटित की गई हैं। जबकि, देशभर में 65 दलहन बीज केंद्र और 50 स्टोरेज यूनिट बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा 13 राज्यों में 130 मॉडल दलहन गांव विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसी तरह तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इनके उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत किया जा रहा है। अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय बजट 2024-25 में आत्मनिर्भरता लाने के लिए तिलहन और दलहन के संबंध में उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है।

खास फसलों के हिसाब से 600 क्लस्टर बनेंगे

तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 तक 10,103.38 करोड़ रुपये (7,481.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ) के आउटले के साथ एक नए कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसके तहत सालाना 10 लाख हेक्टेयर को कवर करते हुए मुफ्त बीज वितरण, किसान प्रशिक्षण, फील्ड स्कूल, मौसम सलाह आदि के लिए 600 फसल विशिष्ट मूल्य श्रृंखला क्लस्टर बनाए जाएंगे।

65 बीज केंद्र और 50 स्टोरेज यूनिट बनेंगी

सालाना 2.8 लाख हेक्टेयर में उन्नत बीज किस्मों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 65 बीज केंद्र और 50 स्टोरेज यूनिट स्थापित की जाएंगी। कटाई के बाद वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों और कारोबारियों का सहयोग किया जाएगा। जबकि, कपास, मक्का, चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। जबकि, 2030-31 तक खाद्य तिलहनों का उत्पादन 69.7 मिलियन मीट्रिक टन, उत्पादकता 2112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और

13 राज्यों में मॉडल दलहन गांव प्रोजेक्ट को मंजूरी

दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए आईसीएआर के केवीके के जरिए 10,780 हेक्टेयर में दालों के क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन (सीएफएलडी) का नया दृष्टिकोण अपनाना लक्ष्य है। खरीफ-2024 के लिए किसानों को एचवाईवीएस दालों की 4.25 लाख मिनीकिट, रबी 2024-25 के लिए दालों की 22.17 लाख मिनीकिट आवंटित की गई हैं। आईसीएआर की ओर से 150 बीज केंद्रों के जरिए 2.25 लाख क्विंटल दालों के उत्तम क्वालिटी के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। केंद्रीय बीज एजेंसियों और आईआईपीआर कानपुर के दलहन बीज केंद्रों के माध्यम से 3.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया है। इसके साथ ही 13 राज्यों के 65 जिलों में 130 मॉडल दलहन गांव विकसित करने के लिए आईसीएआर की ओर से 'मॉडल दलहन गांव' परियोजना को मंजूरी दी गई।

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिए गए सुझाव

सर्दी से फसलों और पशुओं बचाने के लिए करें उपाय, पानी लगाने से पूर्व न करें यूरिया का प्रयोग

लहार। जागत गांव हमार

इस समय पूरे जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात के साथ ही दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे एवं सर्द हवाओं का प्रकोप भी जारी है। ऐसे में जिले के किसानों एवं पशुपालकों को इस सर्दी से अपनी फसलों एवं पालतू पशुओं के बचाव के लिए प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा फसलों एवं पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए सुझाव दिए गए हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि पालतू पशुओं गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को सर्दी से बचाव के लिए रात के समय पशुशाला में ही बांधे। पशुशाला के खिड़की, दरवाजों एवं खुले हुए भाग पर टाट एवं फूस आदि से बनी हुई टटियों से पूरी तरह बंद रखें। शाम के समय पशुशाला में कुछ समय तक आग जलाकर उसे गर्म कर दें। पशुशाला को साफ स्वच्छ एवं सूखा रखें। सप्ताह में एक बार पशुशाला में चूने का छिड़काव तथा नालियों में फिनायल आदि का प्रयोग अवश्य करते रहें। पशुओं को चारा खिलाने वाली नाद साफ एवं सूखी रखें तथा उनकी नियमित सफाई करते रहें। दिन के समय धूप निकलने पर पशुओं को धूप में अवश्य निकालें। आवश्यकता अनुसार पशुओं के शरीर पर धूप में खुरैरा करें। पशुओं को स्वच्छ एवं ताजी पानी ही पिलायें। उन्हें संतुलित आहार खाने को दें। अत्यधिक पानी वाला हरा चारा बरसीम, जई आदि को काटकर एक दिन बाद ही कुट्टी करके खिलाएं। दुधारू पशुओं एवं बकरियों को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए उन्हें शाम के समय गुड एवं मेथी खिलाये। बकरियों को ठंड से बचाव के लिए गुड-मेथी के साथ लहसुन भी खिलाना चाहिए।

फसलों को ठंड एवं पाले के प्रकोप से बचाने के लिए शाम के समय खेतों के चारों तरफमेड़ो पर धुआ करते रहें। आवश्यकता अनुसार फसलों में हल्की से मध्यम सिंचाई करें। फसलों में सिंचाई के रूप में बहुत ज्यादा पानी न लगाए। फसल में पानी लगाने से पूवज़ यूरिया का प्रयोग न करें। यूरिया का प्रयोग फसल में सिंचाई करने के बाद ओठ आने पर ही करें। खड़ी

फसल में डीएपी के प्रयोग से कोई लाभ नहीं होता अतः इस प्रकार की प्रेक्टिस से बचें।

पाले से बचाव के लिए सरसों की फसल में गंधक के अम्ल का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करें। गेहूं में कल्ले, गांठ एवं बालिया बनने की अवस्था में सिंचाई करें तथा खड़ी फसल में सिंचाई उपरांत शेष नत्रजन की नैनो यूरिया द्वारा पूर्ति करें। सरसों की फलियों में दाना बनते समय सिंचाई करें। चने की फसल में फूल आने की अवस्था में सिंचाई कदापि न करें। इससे फूल झड़ जाएगा तथा उत्पादन प्रभावित होगा।

किसान सारथी द्वारा समाधान प्राप्त करें

लहार। किसान फसलों का नियमित परीक्षण करते रहें यदि कोई रोग या बीमारी दिखाई दे रही है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसका समय पर निदान करें। रोग या बीमारी की दशा में कृषि विज्ञान केंद्र अथवा किसान सारथी के टोल फ्री नंबर से 18001232175 संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। किसान सारथी के टोल फ्री नंबर के माध्यम से सीधे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक से परामर्श प्राप्त हो जाता है।

मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ खेती कर रहा है गुना का एमबीए पास किसान

नौकरी से दिया इस्तीफा, पॉलीहाउस में गुलाब उगा रहे हैं डच गुलाब

बंडलों में पैक करके ही इसे पूरे देश में करते हैं सप्लाई

गुलाब और मिर्च की खेती से मशहूर हुए गुना के युवा किसान अंबर लुंबा, देश के बाहर भी उत्पाद की मांग

जागत गांव हमार, गुना।

एक ओर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में लगी है। वहीं दूसरी ओर किसान भी परंपरागत खेती छोड़ नगदी फसल की खेती की ओर झुक रहे हैं। इसी कड़ी में गुना में एमबीए पास किसान अंबर लुंबा अच्छी नौकरी छोड़कर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने डच रोज से खेती की शुरुआत की, अब सब्जियां भी उगा रहे हैं। इस समय उन्होंने लगभग पांच बीघा में लौंगा मिर्च उगाई है। अंबर को एक बीघा में 30 हजार की लागत पर एक लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है।

हैदराबाद से किया एमबीए, 2017 तक की नौकरी

अंबर गुना शहर के ख्यालबाग में रहते हैं। उन्होंने हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से 2013 में एमबीए किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रिलायंस पावर, सिंगरौली में नौकरी मिल गई। 2017 तक नौकरी करते रहे। वे अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते थे। 2017 में नौकरी से इस्तीफा देकर गुना लौट आए। यहां आकर खेती-किसानी का रुख किया। अंबर ने शुरुआत में पारंपरिक खेती की लेकिन इसमें कुछ खास लाभ होता नहीं दिखा। लागत और आमदनी का औसत भी ठीक नहीं था। इसके चलते उन्होंने कुछ अलग हटकर दूसरी खेती करने का सोचा। शहर से 7 किलोमीटर दूर हरिपुर गांव में उनकी जमीन है। यहां उन्होंने सबसे पहले डच रोज उगाया। उसके बाद सब्जियों की खेती करना भी शुरू किया। इस बार उन्होंने पांच बीघा में लौंगा मिर्च लगाई है।

अंबर ने बताया कैसे करते हैं खेत की तैयारी

अंबर ने बताया कि खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले प्लाऊ चलाया जाता है। इसके बाद इसे एक महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर मिट्टी को बारीक करने के लिए खेत में रोटावेटर चलाया जाता है। इससे मिट्टी फूटकर बारीक हो जाती है। उसके बाद एक बीघा में लगभग 3-4 ट्रॉली खाद डालते हैं। फिर बेड तैयार किए जाते हैं। एक बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट होती है। लंबाई खेत के हिसाब से घट-बढ़ सकती है। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 5 फीट रखी जाती है। बेड पर पहले देशी खाद, फिर रासायनिक खाद डाली जाती है। इसमें डीएपी पोटाश, सल्फर शामिल होता है। बेड तैयार होने के बाद ड्रिप के लिए पाइप बिछाकर उस पर पॉलिथीन लगाते हैं। इसे मल्चिंग कहते हैं। फिर पौधे लगाने के लिए एक फीट पर छेद किया जाता है।

अपने खेत पर ही तैयार करते हैं पौध

अंबर लुंबा ने बताया कि मिर्च की पौध वह खेत पर ही तैयार करते हैं। एक ट्रे में देसी खाद मिली हुई मिट्टी डाली जाती है। फिर एक-एक बीज ट्रे के सांचों में लगाया जाता है। उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ ही दिन में पौध तैयार हो जाती है। जो सबसे अच्छी पौध होती है, उसे खेत में लगाया जाता है। बेड के दोनों किनारों पर लकड़ियों के पिलर बनाकर उस पर रस्सियां बांधी जाती हैं। मिर्च का पौधा काफी बड़ा होता है, इस वजह से उसे सपोर्ट देने के लिए प्लास्टिक की रस्सियों का सहारा दिया जाता है, जिससे वह जमीन पर न गिरे।

रोग और कीटों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती

मिर्च में कई तरह के रोग लगते हैं। इनमें पत्ती झुलस, फल सड़न, पाउडरी फफूंद, विल्ट (कवक और जीवाणु), जीवाणु पत्ती धब्बा, विषाणु रोग, लीफ कर्ल वायरस रोग प्रमुख हैं। फफूंद वाला रोग सबसे ज्यादा लगता है। फफूंद वाले रोग में फलों का सड़ना या मर जाना, मुरझाना, सेकोस्पोरा पत्ती धब्बा और पाउडरी फफूंद जैसी कई समस्याएं हैं। इसके अलावा फल छेदक, थ्रेप्स, माइट्स जैसे कीट भी प्रमुख चुनौतियां हैं। अंबर कहते हैं- केवल किसान ही एक व्यक्ति है, जो अपने उत्पाद की कीमत तय नहीं करता है। कैश क्रॉप में सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। किसान का पूरा मुनाफा बाजार के रेट पर निर्भर करता है। अगर अच्छा भाव मिल जाए तो मुनाफा हो जाता है। वहीं, अगर भाव नहीं मिले तो लागत ही बड़ी मुश्किल से निकल पाती है।

एक बीघा में करीब 30 हजार का खर्च

एक बीघा में लौंगा मिर्च उगाने के लिए खेत तैयार करने में लगभग 25 से 30 हजार रुपए की लागत आती है। इसमें खेत तैयार करने से लेकर रखरखाव, पानी, बिजली, खाद, रासायनिक खाद, तुड़ाई के लिए लेबर शामिल होता है। बीज की कीमत अलग होती है। अगर पैदावार ठीक हुई और बाजार में कीमत अच्छी मिली तो 1.5 लाख रुपए तक की पैदावार होती है। सारा खर्च काटकर एक लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा होता है।

तीन महीने में तैयार होती है फसल

मिर्च की फसल तैयार होने में आमतौर पर लगभग 100 दिन लगते हैं। फसल के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। बीज बोने के 22 से 25 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। रोपाई के बाद 55 से 60 दिनों में पौधों में मिर्च आने लगती है। पानी की जरूरत पौधे की उम्र, मौसम और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। सबसे उपयुक्त लाल मिट्टी मानी जाती है।

देश से बाहर भेज रहे गुलाब

अंबर लुंबा पिछले दो वर्षों से डच रोज की खेती भी कर रहे हैं। पॉलीहाउस में गुलाब उगा रहे हैं। एक दिन में लगभग 60-70 बंडल गुलाब का उत्पादन होता है। एक बंडल में 20 गुलाब रहते हैं। बंडलों में पैक करके ही इसे आगे भेजा जाता है। एक बंडल की कीमत एवरेज 100 रुपए तक होती है। सीजन में ज्यादा कीमत भी मिलती है। रोजाना 6-7 हजार रुपए के गुलाब की बिक्री हो रही है। अंबर ने बताया कि गुलाब का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली और जयपुर है। गुना से यहां ट्रांसपोर्ट आसान है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर भी गुलाब भेजे जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि भारत में ही गुलाब के फूलों की खूब डिमांड है। जितना गुलाब उगता है, उसका अधिकतर हिस्सा यहीं खप जाता है। कुछ फूल देश से बाहर भी भेजे जाते हैं।

-एफसीआई से डिस्टलरीज को 550 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता मिलेगा

इथेनॉल बनाने चावल की कीमत घटाई गई 24 लाख टन तक कर सकतीं हैं खरीद

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्र ने नए ईएसवाई ईयर 2025-26 के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 20 फीसदी तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए चावल, मक्का के साथ ही दूसरे मोटे अनाज के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। जबकि, गन्ना से पहले ही इथेनॉल बनाया जा रहा है। अब केंद्र ने इथेनॉल टारगेट पूरा करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए एफसीआई से डिस्टिलरीज को बिक्री किए जाने वाले चावल का दाम 550 रुपए प्रति क्विंटल घटा दिया है। घटी हुई कीमत पर डिस्टिलरीज 24 लाख मीट्रिक टन तक चावल खरीद सकेंगी। इस फैसले के बाद इथेनॉल बनाने की गति में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। खाद्य मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि 2024-25 के दौरान लगभग 110 करोड़ लीटर इथेनॉल के लिए एफसीआई के चावल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और इथेनॉल उत्पादकों के लिए खुले बाजार बिक्री योजना के तहत एफसीआई चावल का आरक्षित मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल घटाकर 2250 रुपये कर दिया। खाद्य मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्य सरकारें और राज्य संचालित निगम 12 लाख टन तक खरीद सकते हैं, जबकि इथेनॉल डिस्टिलरी को कम दर पर 24 लाख टन तक खरीदने की अनुमति है।

पहले 2800 रुपए था चावल का रिजर्व मूल्य

राज्यों और डिस्टलरीज के लिए एफसीआई का पिछला रिजर्व मूल्य 2800 रुपए प्रति क्विंटल था। इसमें 550 रुपए प्रति क्विंटल कीमत कम की गई है, जिसके बाद अब 2250 रुपये में चावल की आपूर्ति हो सकेगी। साप्ताहिक ई-नीलामी के जरिए चावल स्टॉक मैनेज करने वाली संस्था भारतीय खाद्य निगम 30 जून 2025 तक इस संशोधित नीति को लागू करेगा।

निजी मूल्य में कोई बदलाव नहीं

केंद्र के फैसले के अनुसार निजी व्यापारी और सहकारी समितियां 2800 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करना जारी रखेंगी, जबकि नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार जैसी केंद्रीय सहकारी समितियां भारत ब्रांड के तहत बिक्री करने पर 2400 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी.मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओएमएसएस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना और विभिन्न हितधारकों को चावल का कुशल वितरण पक्का करना है।

उत्पादन बढ़ाने पर जोर

इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने के लिए देश को 2023-24 में 545 करोड़ लीटर से अधिक 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करना होगा। एक आधिकारिक नोट के अनुसार 2023-24 में ईएसवाय के दौरान पेट्रोल के साथ 14.6 फीसदी ब्लेंडिंग हासिल किया गया है। गुड़ से इथेनॉल बनाने की 941 करोड़ लीटर क्षमता और अनाज आधारित डिस्टिलरी की क्षमता 744 करोड़ लीटर इथेनॉल है। इथेनॉल बनाने के लिए चावल की कीमत घटाई, एफसीआई से डिस्टिलरीज को 500 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता मिलेगा। खाद्य मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि 2024-25 के दौरान लगभग 110 करोड़ लीटर इथेनॉल के लिए एफसीआई के चावल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केंद्र ने इथेनॉल के लिए एफसीआई से डिस्टिलरीज को बिक्री किए जाने वाले चावल का दाम 550 रुपए प्रति क्विंटल घटा दिया है।

रीवा के 4283 हितग्राहियों को मिले सम्पत्ति कार्ड

स्वामित्व व भू-अधिकार गांव के विकास का बन रहे हैं आधारः राजेंद्र शुक्ल

जागत गांव हमार, भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि देश व प्रदेश में विकास कार्यक्रमों के साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाएँ प्राथमिकता से क्रियान्वित की जा रही हैं और पात्र लोगों को इनका लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में केन्द्र संचालित योजनाओं के साथ ही प्रदेश स्तर पर जनकल्याण के कार्य कराकर लोगों को इनसे लाभान्वित किया जा रहा है। स्वामित्व योजना से पट्टे मिलने से अब हितग्राही उस जमीन से मालिक बन गये और लोगों को पक्का कानूनी अभिलेख भी मिल गया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वामित्व व भू-अधिकार गांव के विकास का आधार बन रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक किये गये पट्टा बनाने व वितरण कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जनवरी तक शेष रह गये हितग्राहियों को भी पट्टे मिल जायेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के 50 हजार से अधिक ग्रामों के 65 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत सम्पत्ति कार्ड का वितरण किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल स्वामित्व योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर निगम टाउन हाल रीवा में शामिल हुए।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्भद्धह्लiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304

4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के लिए युवाओं से आवेदन आमंत्रित

भोपाल। इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिये गए दिशा निर्देशानुसार फसलों की गिरदावरी के लिए अब युवाओं को भी जोड़ा जायेगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाये गये है। फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी कार्य वर्ष में 3 बार (मौसम खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से की जाती है। जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु भारत सरकार द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह प्रत्येक मौसम हेतु लगभग 45 दिन की कार्यवाही होती है। जिसमें जिओ फेंस तकनीक के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। इस योजना में मौसम रबी 2024-25 डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण हेतु सर्वेयर पंजीयन किए जा रहे है। उक्त कार्य हेतु जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो भूलेख पोर्टल पर पंजीयन के लिए पात्र है। इसमें आधार ओटीपी से पंजीकरण भू-लेख पोटर्ल के माध्यम से होगा पटवारी द्वारा ग्राम आवंटन किया जाएगा। युवा द्वारा सारा एप के माध्यम से कार्य किया जायेगा। जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 वीं उतीर्ण निर्धारित की गई है। मोबाइल फोन मय इंटरनेट उपलब्ध होना जरूरी है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)